

कंपनी जगत का लाभ ज्यादा बढ़ा और जीडीपी कम

समी मोडक और सुंदर सेतुरामन
मुंबई, 11 जून

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के तौर पर भारतीय कंपनी जगत का लाभ बढ़कर 15 साल के उच्चस्तर पर पहुंच गया और यह वित्तीय, ऊर्जा और वाहन कंपनियों के लाभ में सुधार की बदैलत हुआ। मोतीलाल ओसवाल के विश्लेषण के अनुसार निफ्टी-500 कंपनियों के लिए लाभ और जीडीपी का अनुपात वित्त वर्ष 2023-24 में बढ़कर 4.8 फीसदी पर पहुंच गया जो वित्त वर्ष 2023 में 4 फीसदी था। ब्रोकरेज ने कहा कि सभी सूचीबद्ध कंपनियों के लिए यह अनुपात 5.2 फीसदी बैठता है। वित्त वर्ष 24 में हुई वृद्धि में वित्तीय, ऊर्जा (तेल व गैस) और वाहन कंपनियों का योगदान 95 फीसदी रहा। निफ्टी-500 कंपनियों का लाभ वित्त वर्ष 2024 में सालाना आधार पर

30 फीसदी की दर से बढ़ा जो वित्त वर्ष 2023 में वार्षिक आधार पर घटकर 9.3 फीसदी रह गया था (यह वित्त वर्ष 2022 में 52 फीसदी था)। वित्त वर्ष 24 में भारतीय कंपनी जगत के लाभ को मजबूती मिली क्योंकि वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही के दौरान वृद्धि की रफ्तार मजबूत बनी रही। वित्त वर्ष 24 की चौथी तिमाही में 200 अग्रणी फर्मों की आय में वृद्धि की रफ्तार सालाना आधार पर 20 फीसदी से ज्यादा रही जो आम राय के अनुमान के मुकाबले करीब 500 आधार अंक ज्यादा है। नीमूरा ने पिछले हफ्ते एक नोट में कहा था कि वित्तीय, वाहन, रियल एस्टेट, पूंजीगत सामान और हेल्थकेयर के मामले में सालाना आधार पर वृद्धि दर मजबूत रही। जिसों खास तौर से धातुओं के अलावा केमिकल व कंज्यूमर स्टेपल के मामले में सालाना वृद्धि की रफ्तार कमजोर रही। आईटी सेवाओं में वृद्धि एक



अंक में यानी नरम रही। नोट में कहा गया है कि वाहन, बिजली, तेल व गैस और इंडस्ट्रियल्स के मामले में आय में अपेक्षा अच्चा रहा वहीं आईटी सेवा, एफएमसीजी और केमिकल के लिए आमराय वाले आय अनुमान में रिकॉर्ड कटौती जारी रही। विशेषज्ञों का मानना है कि इस वित्त वर्ष में भी लाभ और जीडीपी का अनुपात और सुधर सकता है। इक्विनाॅमिक्स के संस्थापक जी. चोकालिङ्गम ने कहा कि वित्त वर्ष 24 में

क्रेडिट की वृद्धि 16 फीसदी थी जबकि परिसंपत्ति की गुणवत्ता भी एक दशक में सबसे अच्छी रही। जब परिसंपत्तियों की गुणवत्ता सुधरती है तो प्रावधान की जरूरत घट जाती होती है और लाभ में मजबूती आती है जिससे लाभ और जीडीपी के अनुपात में वित्तीय क्षेत्र के योगदान में सुधार होता है। कुल मिलाकर लाभ-जीडीपी अनुपात में सुधार होगा क्योंकि आईटी क्षेत्र का लाभ इस वित्त वर्ष में सुधरने के आसार हैं। वित्तीय और वाहन क्षेत्रों का लाभ मजबूत बना रहेगा। दूरसंचार क्षेत्र का लाभ टैरिफ बढ़ाव के कारण मजबूत होगा। सीमेंट क्षेत्र में अगली छमाही में सुधार होगा। इतना ही नहीं, अर्थव्यवस्था में 7 फीसदी से ज्यादा की वृद्धि की उम्मीद है और मॉनसून भी सामान्य रहने की संभावना है। वित्त वर्ष 24 में नॉमिनल जीडीपी सालाना आधार पर 9.6 फीसदी बढ़ा जो कंपनियों के लाभ

की वृद्धि दर से कम है। पिछले दशक के मुकाबले भारतीय कंपनी जगत के लाभ में वृद्धि की दर नॉमिनल जीडीपी वृद्धि की दर के मुकाबले कम रही जिसने इस अनुपात को भी कम किया। हालांकि हाल के वर्षों में कंपनियों के लाभ में वृद्धि ने जीडीपी वृद्धि की दर को पीछे छोड़ दिया है। इसकी वजह शुद्ध लाभ मार्जिन में सुधार रहा हालांकि राजस्व की वृद्धि सुस्त रही। वित्त वर्ष 2011 और वित्त वर्ष 2020 के बीच कंपनियों का लाभ-जीडीपी अनुपात घटता रहा है और अपवाद वाला एकमात्र वित्त वर्ष 2017 था। कौविड के दौरान वित्त वर्ष 20 में यह अनुपात दो दशक के निचले स्तर 2.1 फीसदी पर पहुंच गया था। वित्त वर्ष 2017 में अनुपात सुधरा था क्योंकि ग्लोबल साइक्लिकल्स (मसलन धातु और ऊर्जा) में सुधार हुआ था और सरकारी बैंकों के नुकसान इससे पिछले वर्ष के मुकाबले कम हुए थे।

बढ़ रहा अनुपात

वित्तीय, ऊर्जा और वाहन कंपनियों के लाभ में वृद्धि से सुधार को मिली मजबूती

वित्त वर्ष	लाभ-जीडीपी अनुपात (फीसदी)	वित्त वर्ष	लाभ-जीडीपी अनुपात (फीसदी)
2003	2.7	2014	3.7
2004	3.4	2015	3.2
2005	3.7	2016	2.8
2006	3.8	2017	3.0
2007	4.6	2018	2.7
2008	5.2	2019	2.7
2009	4.0	2020	2.1
2010	4.7	2021	3.3
2011	4.7	2022	4.2
2012	4.1	2023	4.0
2013	3.8	2024	4.8
स्रोत : मोतीलाल ओसवाल		नोट : निफ्टी 500 कंपनियों का अनुपात	

सवाल जवाब

बाकी देशों के मुकाबले लगातार बेहतर प्रदर्शन करेगा भारत

मॉर्गन स्टैनली में मुख्य इविचटी रणनीतिकार (इंडिया) रिधम देसाई ने समी मोडक को साक्षात्कार में बताया कि इंडिया गठबंधन सरकार बनने से सुधार एजेंडे में कोई बाधा नहीं आएगी। मॉर्गन स्टैनली इंडिया इन्वेस्टमेंट फोरम के मौके पर देसाई ने कहा कि वित्तीय समेकन और इन्फ्रास्ट्रक्चर, विनिर्माण को बढ़ावा देने के प्रयासों पर आम बजट में नजर बनी रहेगी। बातचीत के मुख्य अंश:



पिछले सप्ताह हमने काफी उतार-चढ़ाव देखा। क्या बाजार अब स्थिर होंगे? चुनावी नतीजों के दिन निवेशक थोड़े परेशान थे क्योंकि वे सोच रहे थे कि गठबंधन सरकार बनने से समस्या हो सकती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में आपने जो संकेत देखे हैं, उससे अब यह बात नहीं रह गई है। हकीकत में तो यह मोदी 2.0 का ही विस्तार है। गठबंधन सरकार वास्तव में आर्थिक एजेंडे में बहुत बाधक नहीं बनती है क्योंकि इसके लिए संसद में बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। संसद से जुड़े कुछ एजेंडे में थोड़ा वक्त लग सकता है। 'एक राष्ट्र, एक वोट' या समान नागरिक संहिता जैसी चीजें सीधे तौर पर अर्थशास्त्र से नहीं जुड़ी हैं।

आम बजट से आपको क्या उम्मीदें हैं? हमें फरवरी के संदेश की इस पुनरावृत्ति की उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार मजबूत वित्तीय समेकन की ओर बढ़ रही है, और हम पिछले साल की तुलना में कम कर्ज लेंगे। हम एक बार फिर इस बात की पुष्टि देखेंगे कि यह रेलवे जैसे चुनिंदा बुनियादी ढांचे वाले क्षेत्रों पर केंद्रित होगा, जहां अभी और काम किया जाना बाकी है। हमें विनिर्माण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में कुछ संकेत मिलेंगे। मुझे यह भी लगता है कि डीप टेक के प्रति सरकार अपनी प्रतिबद्धता दोहराएगी।

सरकार के बढ़ावे से किन थीमों को फायदा होगा? पहली है निजी क्षेत्र के ऋणदाता। उन्हें मजबूत ऋण वृद्धि का लाभ मिलेगा। दूसरी थीम है कॉरपोरेट क्षेत्र जिसके पास निवेश शुरू करने की गुंजाइश होगी जिसका मतलब है कि औद्योगिक क्षेत्र अच्छा करेगा। हमें उम्मीद है कि वैश्विक निर्यात में भारत की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास करेगी। इससे अगले 5 से 10 वर्षों में अर्थव्यवस्था में विनिर्माण की भागीदारी बढ़ेगी। कई क्षेत्र सरकार के फोकस में हैं। इनमें पीएलआई या जीएसटी को तर्कसंगत बनाना या मंजूरीयों में तेजी लाना शामिल हो सकता है। इनमें रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड

प्रोसेसिंग, लैब डायमंड और अक्षय ऊर्जा शामिल है। सरकार सामाजिक बुनियादी ढांचे पर लगातार जोर देगी, जिसमें गरीबों को नए घर दिलाना, पानी की व्यवस्था या और अधिक शौचालय बनवाना शामिल है। इसलिए यह खपत के लिए अच्छा है। ग्रामीण भारत में वास्तव में बड़ा सुधार आ रहा है। भारत की ऊर्जा खपत भी अगले 10 साल में तेजी से बढ़ेगी।

क्या इन क्षेत्रों, खासकर रक्षा क्षेत्र का मूल्यांकन ज्यादा बढ़ गया है? हाँ, हमेशा ऐसे कुछ शेयर रहे हैं जो जरूरत से ज्यादा बढ़ते हैं। बाद में उनमें गिरावट आती है और आपको नया अवसर मिलता है। हम थीम पर ध्यान केंद्रित करते हैं और फिर शेयर चयन पर ध्यान देते हैं। आपको निश्चित रूप से यह समझना होगा कि कीमत में ऐसा क्या है। अगले चार या पांच साल में आय 20 प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है। इसमें अभी बहुत गुंजाइश है। कुछ शेयर अपनी आय के अनुमान से थोड़ा आगे हो सकते हैं, जबकि अन्य पीछे रह सकते हैं। इसलिए कब खरीदना चाहिए, इसका फैसला पोर्टफोलियो प्रबंधकों पर छोड़ देना ही बेहतर है।

क्या आपने सेंसेक्स के लिए कोई लक्ष्य तय किया है? अगले जून तक हमने सेंसेक्स के लिए 82,000 का लक्ष्य तय किया है। दरअसल, सेंसेक्स आय वृद्धि के मुकाबले कम रिटर्न देगा। दुनिया से जुड़ी हमारी इक्विटी रणनीतियाँ इक्विटी परिसंपत्ति वर्ग पर ज्यादा उत्साहित नहीं हैं और भारतीय बाजार भी इससे अलग थलग नहीं हैं। लेकिन मेरा पक्का मानना यह है कि भारत शेय दुनिया की तुलना में लगातार बेहतर प्रदर्शन करेगा।

आप किन क्षेत्रों पर अंडरवेट है? हम आमतौर पर वैश्विक से जुड़े क्षेत्रों पर कम भरोसा करते हैं और रक्षात्मक रुख अपनाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि स्थानीय चक्रोयाना आधारित क्षेत्र अच्छा प्रदर्शन करेंगे।

कोटक ऑल्टरनेट ने किया 1,445 करोड़ रु. का निवेश

अंजलि सिंह
मुंबई, 11 जून

कोटक महिंद्रा समूह की कोटक ऑल्टरनेट ऐसेट मैनेजर्स ने मैट्रिक्स फार्मा की ओर से किए जा रहे वियाट्रिस एपीआई बिजनेस के अधिग्रहण में 1,445 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की है। अधिग्रहण का यह सौदा कोटक स्ट्रैटजिक सिचुएशन फंड-2 के जरिये हुआ। यह अधिग्रहण मैट्रिक्स को भारत की दूसरी सबसे बड़ी एपीआई कंपनी बना देगा। इस सौदे से मैट्रिक्स की पहुंच विस्तृत शोध और विकास क्षमता तक हो जाएगी, जिसमें 185 से ज्यादा वैज्ञानिकों की टीम और 600 से ज्यादा ड्रग मास्टर फाइल (डीएमएफ) की फाइलिंग शामिल है। अमेरिका व यूरोपीय यूनियन के नियामकों से मंजूरी से मैट्रिक वैश्विक स्तर की अहम दवा कंपनियों के साथ अपने संबंधों का

फायदा उठाने के लिए तैयार है। कोटक ऑल्टरनेट की मदद से मैट्रिक्स को यर्ड पार्टी सेल्स मजबूत बनाने और फार्मास्यूटिकल कॉन्टैक्ट डेवलपमेंट ऐंड मैनुफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के क्षेत्र में और संभावनाएं तलाशने में मदद मिलेगी। कोटक ऑल्टरनेट ऐसेट मैनेजर्स के प्रबंध निदेशक श्रीनी श्रीनिवासन ने कहा कि प्रमुख प्रबंधन के साथ अहम खरीद कोटक ऑल्टरनेट की सौदे की सोर्सिंग व स्ट्रक्चरिंग की क्षमता को दर्शाती है। साथ ही यह दवा उद्योग में हमारी विशेषज्ञता और मजबूत एपीआई कारोबार के लिए प्लेटफॉर्म बनाने की क्षमता बताती है, जिसकी हम खुद के दम पर और विलय-अधिग्रहण के जरिए वृद्धि कर सकते हैं। (डिस्क्लेमर : बिज़नेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड में कोटक समूह के नियंत्रण वाली इकाइयों की बहुलांश हिस्सेदारी है)

राहुल भाटिया ने बेचा इंटरग्लोब का हिस्सा

इंटरग्लोब एविएशन की सबसे बड़ी हिस्सेदारी इंटरग्लोब एंटरप्राइजेज ने 2 फीसदी हिस्सेदारी 3,367 करोड़ रुपये में बेच दी। सह-संस्थापक राहुल भाटिया फैमिली की होल्डिंग कंपनी ने 77.2 लाख शेयर 4,362 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बेचे। सिटीग्रुप ने 1,362 करोड़ रुपये में 31 लाख शेयर खरीदे जबकि अन्य खरीदारों के नाम का खुलासा नहीं किया गया है। इंटरग्लोब का शेयर एनएसई पर 4.2 फीसदी गिरकर 4,374 रुपये पर बंद हुआ। हिस्सेदारी बिक्री से पहले प्रवर्तक इकाई इंटरग्लोब एंटरप्राइजेज के पास इंटरग्लोब की 37.75 फीसदी हिस्सेदारी थी। मार्च में एक अन्य सह-संस्थापक राकेश गंगवाल ने इंटरग्लोब की 6 फीसदी हिस्सेदारी यानी 2.3 करोड़ शेयर 3,016 रुपये प्रति शेयर पर बेचकर 6,786 करोड़ रुपये जुटाए थे। बीएस

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA. INITIAL PUBLIC OFFER OF EQUITY SHARES ON THE MAIN BOARD OF STOCK EXCHANGES IN COMPLIANCE WITH THE CHAPTER II OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018 AS AMENDED ("SEBI ICDR REGULATIONS")



PUBLIC ANNOUNCEMENT

QUADRANT FUTURE TEK LIMITED

Our Company was incorporated as 'Quadrant Cables Private Limited' on September 18, 2015 at Mohali, Punjab as a private limited company under the Companies Act, 2013. Thereafter, the name of our company was changed from 'Quadrant Cables Private Limited' to 'Quadrant Future Tek Private Limited', and a fresh certificate of incorporation dated October 08, 2021 was issued by Registrar of Companies, Punjab and Chandigarh ("RoC"). Subsequently, our Company was converted into a public limited company, the word 'private' was struck off from the name of our Company and consequently, a fresh certificate of incorporation dated October 21, 2021 was issued by the RoC, recording the change of our Company's name to 'Quadrant Future Tek Limited'. For details of change in the name and registered office of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page 205 of the Draft Red Herring Prospectus dated June 02, 2024 ("DRHP") filed with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI")

Corporate Identity Number: U74999PB2015PLC039758

Registered & Corporate Office: Village Basma Tehsil Banur, Distt Mohali - 140 417, Punjab, India;

Contact Person: Ankit Kumar, Company Secretary and Compliance Officer; Telephone: +91 1762 245509;

E-mail: cs_qftl@quadrantfuturetek.com; Website: www. quadrantfuturetek.com

OUR PROMOTERS: MOHIT VOHRA, AMIT DHAWAN, AMRIT SINGH RANDHAWA, RUPINDER SINGH, VISHESH ABROL, VIVEK ABROL, AIKJOT SINGH AND RAJBIR SINGH RANDHAWA



(Please scan this QR Code to view the DRHP)

INITIAL PUBLIC ISSUE OF UP TO [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH (EQUITY SHARES) OF QUADRANT FUTURE TEK LIMITED (OUR COMPANY) FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE) (ISSUE PRICE) AGGREGATING UP TO ₹ 2,750.00 MILLION (ISSUE). THE ISSUE SHALL CONSTITUTE [●]% OF OUR POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹ 10 EACH AND THE ISSUE PRICE IS [●] TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGER AND WILL BE ADVERTISED IN ALL EDITIONS OF [●], AN ENGLISH LANGUAGE NATIONAL DAILY WITH WIDE CIRCULATION, ALL EDITIONS OF [●], A HINDI LANGUAGE NATIONAL DAILY WITH WIDE CIRCULATION AND ALL EDITIONS OF [●], A PUNJABI DAILY NEWSPAPER (PUNJABI BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF PUNJAB, WHERE OUR REGISTERED OFFICE IS LOCATED), AT LEAST 2 WORKING DAYS PRIOR TO THE BID / ISSUE OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO THE BSE LIMITED (BSE) AND THE NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED (NSE, AND TOGETHER WITH BSE, THE STOCK EXCHANGES) FOR THE PURPOSE OF UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES, IN ACCORDANCE WITH THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED (SEBI ICDR REGULATIONS).

In case of any revision in the Price Band, the Bid / Issue Period will be extended by at least 3 additional Working Days after such revision in the Price Band, subject to the Bid / Issue Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company in consultation with the BRLM, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid / Issue Period for a minimum of 3 Working Days, subject to the Bid / Issue Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid / Issue Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a press release, and also by indicating the change on the website of the BRLM and at the terminals of the other members of the Syndicate and by intimation to the Self-Certified Syndicate Banks ("SCSBs"), the Designated Intermediaries and the Sponsor Banks as applicable.

The Issue is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b) of the SCRR read with Regulation 31 of the SEBI ICDR Regulations and in accordance with the Regulation 6(2) of the SEBI ICDR Regulations wherein not less than 75% of the Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to qualified institutional buyers (QIBs) (such portion referred as QIB Portion), provided that our Company, in consultation with the BRLM, may allocate up to 60% of the QIB Portion to the Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations (Anchor Investor Portion), of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from the domestic Mutual Funds. at or above the price at which allotment is made to the Anchor Investors (Anchor Investor Allocation Price). Further, in the event of under-subscription, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the QIB Portion (other than the Anchor Investor Portion) (Net QIB Portion). Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis only to Mutual Funds (Mutual Fund Portion), and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders (other than Anchor Investors), including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to all QIBs. Further, not more than 15% of the Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Investors out of which (a) one-third of such portion shall be reserved for applicants with application size of more than ₹ 0.20 million and up to ₹ 1.00 million; and (b) two-third of such portion shall be reserved for applicants with application size of more than ₹ 1.00 million, provided that the unsubscribed portion in either of such sub-categories may be allocated to applicants in the other sub-category of Non-Institutional Investors and not more than 10% of the Issue shall be available for allocation to Retail Individual Investors in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received from them at or above the Issue Price. All potential Bidders (except Anchor Investors) are mandatorily required to participate in the Issue through the Application Supported by Blocked Amount (ASBA) process by providing details of their respective ASBA accounts, and UPI ID in case of UPI Bidders using UPI Mechanism, as applicable, pursuant to which their corresponding Bid Amount will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks (SCSBs) or by the Sponsor Bank(s) under the UPI Mechanism, as the case may be. Anchor Investors are not permitted to participate in the Anchor Investor Portion through the ASBA process. For further details, see 'Issue Procedure' on page 420.

This public announcement is being made in compliance with the provision of Regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that our company is proposing, subject to applicable statutory and regulatory and requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offering of its Equity Shares and has filed the DRHP with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") on June 11, 2024. Pursuant to regulation 26(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DRHP filed with SEBI shall make public for comments, if any, for a period of at least 21 (twenty one) days from the date of such filing, by hosting it on the website of SEBI at www.sebi.gov.in on the website of Book Running Lead Manager ("BRLM") i.e. Sundae Capital Advisors Private Limited at www.sundaecapital.com and on the website of our company at www.quadrantfuturetek.com and the stock exchanges where the Equity Shares are proposed to be listed, i.e. BSE at www.bseindia.com and NSE at www.nseindia.com Our company hereby invites the public to give their comments on the DRHP filed with the SEBI in respect of disclosures made on the DRHP. The members of the public are requested to send a copy of comments to SEBI. To the Company Secretary and Compliance Officer of our Company and the BRLM at their respective addresses mention herein. All comments must be received by our Company or the BRLM in relation to the offer on or before 5 p.m. on the 21st day from the aforementioned date of filing of the DRHP with SEBI.

Investment in equity and equity related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investor should read the offer document carefully, including the Risk Factors on page 31 of the offer document before making any investment decision. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Issue including the risks involved. The securities have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of this document.

Any decision to invest in the equity shares described in the DRHP may only be taken after a Red Herring Prospectus ("RHP") has been filed with the ROC and must be made solely on the basis of such RHP the equity shares, when offered through the RHP, are proposed to be listed on the BSE and NSE.

For details of shares capital and capital structure of the Company, and the names of the signatories to the Memorandum of Association and the number of shares subscribed for by them see "Capital Structure" on page 84 of the DRHP. The liability of the members of our company is limited.

For the details of the main objects of our company as contained in the Memorandum of Association, see "History and Certain Corporate Matters" on page 205 of the DRHP.

BOOK RUNNING LEAD MANAGER	REGISTRAR TO THE OFFER
SUNDÆ Sundae Capital Advisors Private Limited 404, 4th floor, Vaibhav Chambers Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai - 400 051, Maharashtra, India Tel. No. 96 6785 9191 / +91 22 3501 4499 Email: quadrant ipo@sundaecapital.com Investor Grievance e-mail id: grievances.mb@sundaecapital.com Website: www.sundaecapital.com SEBI Regn. No.: INM000012494 Contact Person: Anchal Lohia / Rajiv Sharma	LINK Intime Link Intime India Private Limited C-101, 1st Floor, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West) Mumbai - 400 083, Maharashtra, India Tel.: + 91 81 0811 4949 E-mail ID: quadrant.ipo@linkintime.co.in Website: www.linkintime.co.in SEBI Regn. No.: INR000004058 Contact Person: Pradnya Karanjekar

All Capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning ascribed to them in the DRHP.

For Quadrant Future Tek Limited
on behalf of the Board of Directors

Sd/-
Mohit Vohra
Managing Director

Date: June 11, 2024
Place: Basma, Mohali

QUADRANT FUTURE TEK LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offering of its Equity Shares and has filed the DRHP with SEBI on June 11, 2024. The DRHP is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively on the website of company at www. quadrantfuturetek.com and on the website of BRLM i.e. Sundae Capital Advisors Private Limited at www.sundaecapital.com. Any potential investor should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, see the section entitled "Risk Factors" on page 31 of DRHP. Potential investors should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decision.

This announcement is not an offer of securities for sale in the United States elsewhere. This announcement has been prepared for publication in India only and is not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States. The equity shares offered have not been, and will not be registered under U.S. Securities Act of 1993, as amended (the "U.S. Securities Act") or any state law of United States and may not be offered or sold with the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable U.S. state Securities law, Accordingly the Equity Shares are only being offered and sold (a) in the United States only to "qualified institutional buyers" (as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act) in transactions exempt from, or not subject to the registration requirements of the U.S. Securities Act and (b) outside the United States in "Offshore transactions" in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act, and the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales occur.